Rajasthan Foundation Newsletter
राजस्थान फाउण्डेशन पत्रिका

राजस्थान फाउण्डेशन
Rajasthan Foundation

July, 2009

हरित राजस्थान - प्रदेश को हरा-भरा बनाने की अभिनव पहल

हरित राजस्थान प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए जन-जन के सहयोग से वृक्षारोपण करने की एक महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय (2009-10 से 2013-14) योजना है। इस योजना की घोषणा प्रदेश की सरकार ने की है। औपचारिक रूप से यह योजना जुलाई, 2009 से आरम्भ हो गई है।

राज्य सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने व राज्य के वनस्पति आच्छादित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से राजकीय, अराजकीय संगठनों व राज्य की जनता के सहयोग से यह पंचवर्षीय योजना आरम्भ की है।

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वृक्षारोपण के उपयुक्त सभी स्थानों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, आवासी क्षेत्रों तथा सरकारी व निजी संस्थाओं के अहातों व खाली पड़े भूखण्डों, सरकारी भूमि, वन एवं चारागाह भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

हरित राजस्थान के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी (नरेगा) योजनान्तर्गत सघन वृक्षा-रोपण, वन संरक्षण एवं चारागाह विकास के कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकेगा बल्कि पर्यावरण की रक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति भी की जा सकेगी।

राज्य में वनस्पति आच्छादित क्षेत्र बढ़ने से, जलवायु परिवर्तन से होने वाले संकटों व जलाभाव की समस्या से निज़ात मिलेगी। वानस्पतिक आवरण पर्याप्त होने से प्राकृतिक आपदाएं यथा बाढ़, सूखा, उपजाऊ मृदा का नष्ट होना तथा पेयजल की कमी से भी आसानी से निपटा जा सकता है।

ग्रामीण विकास विभाग राज्य के स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग होगा।

संदेश

आज मुझे राजस्थान फाउण्डेशन के माध्यम से आप सभी प्रवासी राजस्थानी बन्धुओं से संवाद करते हुए प्रसन्नता हो रही है। राजस्थान फाउण्डेशन गत कई वर्षों से प्रवासी समुदाय व राज्य के बीच में एक सेतु की भूमिका का कार्य अत्यन्त कुशलता के साथ कर रहा है। राजस्थान के प्रवासी समुदाय को राज्य से पुनः जोड़ने की यह पहल अल्प समय में एक लम्बी यात्रा कर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। विश्व भर में फैला प्रवासी समुदाय राज्य के विकास में अहम् एवं अत्यन्त सराहनीय भूमिका निभा रहा है।

राज्य सरकार का यह संकल्प है कि राज्य में सुशासन, पारदर्शी व जवाबदेही प्रशासन हो एवं राजस्थान को आने वाले वर्षों में सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक विकास के पथ पर आगे ले जाए। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विकास और जनकल्याण के सकारात्मक चिन्तन एवं दूरदृष्टि से किये गए सरकार के अहम् फैसलों से निश्चित ही जहां राजस्थान आगे बढ़ेगा, वहीं आमजन को भी राहत मिलेगी। इसी दिशा में सरकार ने हरित राजस्थान, नरेगा (National Rural Guarantee Employment Act) जैसी लोक कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे सीमित संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग कर राज्य का चहुँमुखी विकास होगा।

राजस्थानी प्रवासी बन्धुओं को राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं एवं विनिवेश सम्बन्धित समग्र उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराने के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप विश्वपटल पर राजस्थान एक आदर्श, अग्रसर एवम् विकसित राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा - ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।

आइए, हम और आप मिलकर एक गतिशील एवं समृद्ध राज्य के लिए निरन्तर प्रयासरत रहें।

शुभकामनाओं सहित!

(राजेन्द्र पारीक)

मंत्री, उद्योग एवं अप्रवासी भारतीय विभाग, राजस्थान सरकार

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (राज्य मंत्री)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अतिरिक्त प्रभार)

श्री रामलाल जाट (राज्य मंत्री)

वन एवं पर्यावरण, खनिज (अतिरिक्त प्रभार)

श्री ब्रह्मदेव कुमावत

संसदीय सचिव

श्री दिलीप चौधरी

संसदीय सचिव

श्री नानालाल नीनामा

संसदीय सचिव

नरेगा - ग्रामीण अंचलों में रोजगार मुहैय्या कराने की प्रभावी योजना

"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, 2006 (National Rural Employment Guarantee Scheme - NREGA)" राजस्थान में लागू की गई है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारन्टीशुदा रोजगार मुहैय्या कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के अन्य उद्देश्य, यथा, रोज़गार गारंटी से सम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण औरतों के सशक्तिकरण, गांवों से शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना भी है। इस योजना की सफल क्रियान्विति की सुनिश्चिति हेतु राज्य सरकार द्वारा यथोचित एवम् सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं। यह क्रियान्वयन प्रक्रिया जन-समुदाय को आकर्षित करने में सक्षम रही है। पंचायतें भी स्थानीय जन समुदाय की मांगों के अनुरूप कार्यों को चिह्नित करने की दिशा में सक्रिय हैं। परिणामस्वरूप, इस योजना के तहत् मुख्यतः ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया गया है जो ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं, सामुदायिक सम्पत्ति आधार, एवम् लघु सिंचाई परियोजनाओं से सम्बद्ध हों।

नरेगा की भारत के 200 जिलों में क्रियान्विति के समय राजस्थान के छः पिछड़े जिले चुने गये थे। ये जिले थे - बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर, करौली तथा सिरोही। द्वितीय चरण में छः अन्य जिले चुने गए थे - बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर एवम् टोंक।

राजस्थान ने, जहां एक ओर, रोजगार के अवसर मुहैय्या कराने में आशातीत सफलता अर्जित की है, महिलाओं को सम्मिलित करते हुए, समाज के पिछड़े तबके के कल्याणकारी अभ्युदय को भी भरपूर प्राथमिकता दी है। रोजगार के मामले में, राज्य में, महिलाओं का अंशदान दो-तिहाई है, जो कि अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को भी रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान किए गए हैं, जो कि उनके जीवनस्तर को कहीं ऊँचा उठाने में कारगर सिद्ध हुए हैं।

चूंकि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, जल संरक्षण योजनाओं, यथा, नहरों के गहरीकरण, जल-संचयन प्रणाली एवम् जल-निकासी प्रबन्धन को भरपूर प्राथमिकता दी जाती रही है। राज्य के कुछ भागों में इन परियोजनाओं का कोष लघु बांध परियोजनाओं, जल संग्रहण, वन विकास एवम् पौधारोपण के रूप में व्यय किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप भू-कटाव को रोकने एवम् जल-संरक्षण में काफी सहायता मिली है।

नरेगा परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप विभिन्न सकारात्मक पहलू उजागर हुए हैं - यथा, प्रवास में गिरावट, ग्रामीण परिसम्पत्तियों का सृजन, महिलाओं की वृद्धिगत सहभागिता, ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक एवम् पारस्परिक सहभागिता आदि।

राज्य का नया नेतृत्व : एक परिचय

श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री

वित्त एवं करारोपण, आयोजना (जनशक्ति), नीति निर्धारण, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान राज्य एवं अन्वेषण ब्यूरो, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खादी एवं ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन एवं अन्य

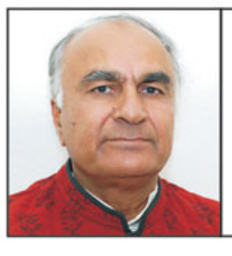

श्री ऐमादुद्दीन अहमद 'दुर्रू मियां'

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा

श्री भरत सिंह

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

श्रीमती बीना काक

महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, कला-संस्कृतिक एवं पुरातत्व, मुद्रण एवं लेखन सामग्री

श्री ब्रजकिशोर शर्मा

यातायात, संस्कृत शिक्षा, भाषा एवं भाषायी अल्पसंख्यक एवं देवस्थान (अतिरिक्त प्रभार)

हरजीराम बुरड़क

कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन

श्री हेमाराम चौधरी

राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय

जनजाति क्षेत्रीय विकास, जन अभियोग निराकरण, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा (अतिरिक्त प्रभार)

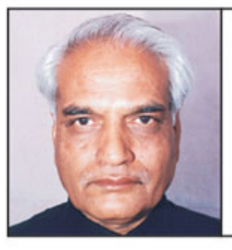

श्री महीपाल मदेरणा

जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल, सिंचित क्षेत्रीय विकास

मास्टर भंवर लाल

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, श्रम एवं नियोजन

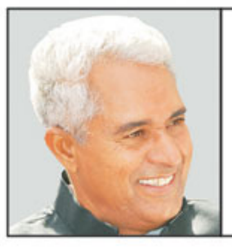

श्री परसादी लाल मीणा

सहकारिता, अल्प बचत एवं स्टेट लॉटरी गृह एवं नागरिक सुरक्षा

श्री शांति कुमार धारीवाल

गृह, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य, नगरीय विकास एवं आवासन (अतिरिक्त प्रभार) तथा स्वायत्त (अतिरिक्त प्रभार)

डॉ. जितेन्द्र सिंह

ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (अतिरिक्त प्रभार) एवं उच्च शिक्षा (अतिरिक्त प्रभार)

श्री राजेन्द्र पारीक

उद्योग, अप्रवासीय भारतीय, राजकीय उपक्रम, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा आबकारी (अतिरिक्त प्रभार)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री)

कारागार (स्वतंत्र प्रभार) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

श्रीमती गोलमा देवी (राज्य मंत्री)

खादी एवं ग्रामोद्योग, गृह रक्षा, एवं नागरिक सुरक्षा

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री)

वक्फ (स्वतंत्र प्रभार)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

श्री अशोक बैरवा (राज्य मंत्री)

सूचना एवं जन सम्पर्क (स्वतंत्र प्रभार) राज्य बीमा (स्वतंत्र प्रभार) निर्वाचन (स्वतंत्र प्रभार) यातायात, संस्कृत शिक्षा, भाषा एवं भाषायी, अल्पसंख्यक और देवस्थान

श्री बाबू लाल नागर (राज्य मंत्री)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, डेयरी एवं तकनीकी शिक्षा (कृषि) अतिरिक्त प्रभार

श्री भरोसी लाल जाटव (राज्य मंत्री)

सम्पदा (स्वतंत्र प्रभार), मोटर गैराज (स्वतंत्र प्रभार) कृषि, पशुपालन और मत्तस्य

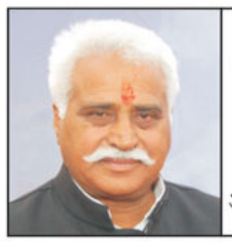

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री)

कृषि विपणन (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू-जल एवं सिंचित क्षेत्र विकास

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री)

युवा मामले एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, श्रम एवं नियोजन

Silicon complex in Bikaner by VAVASI Telegence Pvt. Ltd.

VAVASI Telegence Private Limited, a UAE based company, has inked Memorandum of Understanding (MoU) with state government in March 2009 for setting up a new silicon manufacturing complex in Bikaner. The investment in setting up this silicon manufacturing complex will be of Rs 45,000 crores.

This investment will see Bikaner developing as a hub for silicon chips and solar photovoltaic films production. According to the officials at VAVASI, the new complex will have 20,000 MT of Mono-Crystalline, 2000 MW Mono-Crystalline PV modules, 240 MW thin film Photo Voltaic manufacturing capacity and a Float Glass Plant. According to the promoters with the allotted coal block, a 2,000 MW thermal power plant would also be setup, out of which only 750 MW of power would be used by the project and the balance of it would be fed to the national grid.

As on date, only seven countries in the world produce total of 3,700 MW per annum of capacity, wherein after the setting up of this complex India alone would be producing 2,500 MW per annum capacity.

The Group, while signing the MoU had claimed that the project will help to pump in the state's economy by USD 50 billion over a period of 7 years if 50% of the product is exported and likely to create 16,500 direct and 64,000 indirect jobs.

Shri Manohar Kant assigned additional charge of Commissioner, Rajasthan Foundation

Shri Manohar Kant a senior I.A.S. officer (1983 batch) has recently joined as the Commissioner, Rajasthan Foundation. He has held various posts of responsibility in Government including CEO, Municipal Corporation, Jaipur ; Secretary to Government, Sports & Youth Affairs Department, Rajasthan, Jaipur ; Secretary to Government, Labour & Employment Department, Rajasthan, Jaipur; Divisional Commissioner, Kota & Jodhpur; Special Secretary to Government, Revenue Department, Rajasthan, Jaipur; Collector & District Magistrate, Alwar and Rajasamand, to name a few. Besides having this administrative experience, he also has the professional degree of MBA (Sydney, Australia) Under his dynamic leadership, Rajasthan Foundation is sure to achieve its objective.

वैबपोर्टल पर निःशुल्क सदस्यता की सुविधा

राजस्थान फाउण्डेशन समस्त प्रवासी राजस्थानी बन्धुओं से आग्रह करता है कि वह फाउण्डेशन के वेबपोर्टल पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर सदस्य बन सकते हैं जिससे वह राज्य एवं फाउण्डेशन की गतिविधियों से समय-समय पर अवगत हो सकें।

Rajasthan Budget : 2009-10 Highlights

Hon'ble CM Ashok Gehlot presented state budget on July 8, 2009. The major thrust of the budget is on development of the BPL category, girls education, medical facilities and infrastructure. Some of the highlights of Rajasthan Budget are:

- Allocation increase for Roads, Power, Agriculture and Water resources.
- Medical facilities for BPL families and upgradation of hospitals.
- 15000 km National Highways for state.
- Recruitments in Health, Education, Police, Rural Development.
- Focus on rural poor and common man.
- Free food grains for tribal areas.
- 3% of plan allocation to be spent on peoples centric IT projects.
- More than 6000 IT enabled service centres in rural areas.
- Secondary education coverage in all Panchayat Head Quarters.
- Increase in mess allowance and scholarships of SC/ST students.
- Veterinary University in Bikaner.
- Engineering College in Banswara.
- Jaipur to be developed as a World Class City.
- 1.25 lac Housing Units to be built in the next five years.
- New Industrial Policy, Forest Policy, Water Policy and Mineral Policy.
- Higher Education Reforms Commission, Council of Vocational Education and Training.
- Tourism Act.
- Emphasis on Drinking Water Schemes, Health Schemes and strengthening of Educational Infrastructure. Thrust on Vocational Training and Employment.
- Environment Policy, Massive Plantation Drives.

Rajasthan Foundation looks forward to hearing from you. Kindly get in touch with us at Rajasthan Foundation
Yojana Bhawan, Yudhisther Marg, C-Scheme, Jaipur 302005, Rajasthan, India.
Tel +91-141-2229091, Commissioner (Direct) : +91-141- 2229111,
Executive Director (Direct) : +91-141-2229444, Fax : +91-141-5113224
E-mail: rajfound-rj@nic.in, Website: www.rajasthanfoundation.org
(For Private Circulation)

Designed and Printed at Kumar and Company, Jaipur